हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है।

– अज्ञात

उपद्रवी तत्वों की साजिश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस नागरिकता कानून के मुद्दे पर झूठ फैला रही है और मुसलमानों में भय पैदा कर रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने प्रदर्शनों को प्रायोजित बताया।

आरोही

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों का दायरा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे। दिल्ली में हालात बिगड़ने की आशंका में प्रशासन को कुछ देर के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा और 19 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद करने पड़े। समय पर यात्रियों के एयरपोर्ट न पहुंच पाने के कारण हवाई यातायात में भी व्यवधान पहुंचा। कई जगहों से हिंसा की खबरें भी आई हैं। कुछ जगहों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया और कुछ वरिष्ठ नेताओं, बुद्धिजीवियों और नागरिकों को हिरासत में लिया। इस मुद्दे पर जामिया और फिर देश के कई विश्वविद्यालयों में भड़के आक्रोश को सरकार ने गंभीरता से लिया होता तो हालात शायद इतने न बिगड़ते।

लेकिन छात्रों के आंदोलन को वह सिरे से नकारती रही और इसे उपद्रवी तत्वों की साजिश बताती रही। अब जाकर सरकार ने अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों को नागरिकता कानून के बारे में बताना शुरू किया है। इससे पहले मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का शत–प्रतिशत हाथ होने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस नागरिकता कानून के मुद्दे पर झूठ फैला रही है और मुसलमानों में भय पैदा कर रही है। बीजेपी के कई नेताओं ने प्रदर्शनों को प्रायोजित बताया। लेकिन यह बात लोगों के गले नहीं उतरी क्योंकि खुद बीजेपी के सहयोगी दलों ने ही नागरिकता कानून पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।

असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत ने साफ कहा कि हमारी पार्टी ने नागरिकता कानून के पक्ष में वोट करके गलती की। उन्होंने असम में बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने तक की चेतावनी दी है। जेडीयू ने संसद में साथ दिया लेकिन पार्टी के रसूखदार नेता प्रशांत किशोर ने इसकी आलोचना की, जिसका पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार ने खंडन भी नहीं किया। जेडीयू के कई नेता बिहार में एनआरसी लागू न करने की बात कह चुके हैं। ओडिशा में बीजेडी का भी यही स्टैंड है, और अब शिरोमणि अकाली दल ने कह दिया है कि सीएए में मुसलमानों को भी शामिल किया जाए क्योंकि हमारा देश सेक्युलर है।

तमिलनाडु में बीजेपी के सहयोगी दल एआईडीएमके में इस पर मतभेद जाहिर हो चुके हैं। पार्टी के एक सांसद ने साफ कहा कि इस कानून पर उन्हें सख्त आपत्ति है और अमित शाह देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जाहिर है, देश भर में सीएए और एनआरसी को लेकर गहरी शंकाएं हैं। यह बिल्कुल संभव है कि विपक्षी दल जनता के आक्रोश का जायज और कुछेक अराजक तत्व जहां–तहां नाजायज फायदा उठा रहे हों, लेकिन इससे मामले की गंभीरता कम नहीं होती। सत्तारूढ़ दल को इसे नाक का सवाल न बनाकर लोगों की आपत्तियों को समझना चाहिए और सत्ताशीर्ष को आगे आकर जनता से सीधा संवाद करना चाहिए।

अपना धर्म

धर्म-दर्शन

मनमोहन। यदि आंकड़ों को देखें तो 2011 में लगभग 29 लाख ऐसे भी लोग हैं जिन्होने अपना धर्म नहीं घोषित किया है। मेरा विश्वास है कि ये "हाइ सोसाइटी" में शामिल ऐसे हिन्दू ही होंगे जो हिन्दू कहलाने में शर्म महसूस करते हैं और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द के साथ सहज रहते हैं. यहाँ विचारयोग्य तथ्य है मुस्लिम आबादी में बढ़ती वृद्धि की दर. लगभग 25: की दर से बढ़ती मुस्लिम आबादी सन 2050 तक भारतीय जनसंख्या की लगभग 20 प्रतिशत या अधिक होगी, वहीं हिन्दू आबादी 74 प्रतिशत या इससे भी कम होने की आशंका है। मैने इस धर्म आधारित जनसर्वेक्षण के बाद पूरे विश्व में विभिन्न धर्मों के आंकड़े इकट्ठे किये हैं. भारत की भयावह स्थिति केवल संकेत मात्र है। यही स्थिति पूरे विश्व की हो रही है। विश्व के 22 देशों को छोड़ कर बाकी सभी देशों में वहां की मूल बहुसंख्य आबादी में तेजी से कमी आ रही है, जबकि मुस्लिम आबादी में तेज वृद्धि देखी जा रही है।

संपादकीय

आज भी राजशाही

जापान में सम्राट अकीहितो के पदत्याग के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र प्रिंस नारुहितो ने उनका पदभार ग्रहण किया। जापान दुनिया के उन गिने–चुने देशों में है जहां आज भी, नाममात्र के लिए ही सही पर राजशाही चल रही है। उन चुनिंदा देशों में भी यह इस मायने में खास है कि यहां का प्राचीन राजवंश इतिहास के तमाम उतार–चढ़ाव झेलते हुए भी अपनी निरंतरता बनाए हुए है। 1868 के बहुचर्चित मेइजी रेस्टोरेशन से जापान की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण प्रक्रिया का ऐसा समावेश हुआ, जिसने बदलती दुनिया के साथ जापानी राजशाही का अच्छा तालमेल बनाए रखा। शीर्ष स्तर पर प्राचीन प्रतीकों की मौजूदगी के बावजूद जापान ने तकनीक पर अपनी पकड़ कभी ढीली नहीं होने दी। नतीजा यह कि इस द्वीपीय देश ने जहां बीसवीं सदी की शुरुआत में ही रूस को हराकर यूरोप की अपराजेयता का मिथक तोड़ा, वहीं अपनी भौगोलिक सीमा का आश्चर्यजनक विस्तार भी किया।

हालांकि पहले और दूसरे विश्वयुद्ध में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की उसे भयानक कीमत चुकानी पड़ी। इसके बाद जब जापान ने सैन्यवादी पराक्रम से तौबा की तो आर्थिक क्षेत्र में विकास की चमचमाती मिसाल खड़ी कर दी। इसका कुछ श्रेय सम्राट नाम की उस संस्था को भी जाता है, जो जापानी समाज की स्थिरता के प्रतीक के रूप में जापानियों के दिलो–दिमाग में काफी ऊंचा मुकाम रखती है। एशिया के गणतांत्रिक देशों से तुलना की जाए तो लोगों की एकजुटता और समर्पण की ऐसी मिथकीय कहानियां और कहीं भी नहीं मिलतीं। बहरहाल, नारुहितो का जापान उस जापान से बहुत अलग है जो उनके पिता अकीहितो ने उत्तराधिकार में पाया था। अच्छा होगा कि उनके नेतृत्व में जापानी समाज अपने आधुनिक मूल्यों के लिए जाना जाए।

परदे के पीछे चली तेज कूटनीतिक गतिविधियों से चीन को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के नाम पर आतंकवाद को संरक्षण देने वाली महाशक्ति की छवि बनना उसके लिए अच्छा नहीं होगा।

भारतीय कूटनीति की जीत

रवि शाह

आखिर आतंकवादी संगठन जैश–ए–मोहम्मद के सरगना और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ग्लोबल टेररिस्ट्स की अपनी सूची में शामिल कर लिया। निश्चित रूप से यह भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है। पुलवामा हमले के ठीक बाद मार्च में की गई यह पहल पिछले अनेक प्रयासों की तरह चीन के वीटो की वजह से नाकाम हो गई थी। मगर भारत ने उसके बाद भी कोशिशें जारी रखीं। आतंकवाद पर अंकुश लगाने के इन प्रयत्नों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई देशों का खुला साथ मिला। परदे के पीछे चली तेज कूटनीतिक गतिविधियों से चीन को अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के नाम पर आतंकवाद को संरक्षण देने वाली महाशक्ति की छवि बनना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी जो भी शंकाएं थीं उन्हें दूर करने में भी बाकी देशों ने सक्रिय भूमिका निभाई। नतीजा यह रहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर मसूद अजहर का बचाव करने या इस मसले को टालते जाने वाला कोई नहीं रह गया।

याद करें तो मुंबई हमले की साजिश रचने के

मुख्य आरोपी हाफिज सईद का नाम वैश्विक आतंकियों की इस सूची में पहले से ही शामिल है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद 10 दिसंबर 2008 को उसे इस सूची में डाल दिया गया था। दोनों मामलों में एक बड़ा फर्क यह है कि हाफिज का कश्मीर से लेना–देना नहीं था, जबकि मसूद अजहर इस लिस्ट में डाला जाने वाला वह पहला आतंकी है, जिसकी पहचान जम्मू–कश्मीर की आतंकी गतिविधियों से जुड़ी है। इससे यह साबित होता है कि दुनिया भारत की राय को तवज्जो देते हुए कश्मीर मसले को आतंकवाद से जुड़ी समस्या के रूप में देखने लगी है। मामले का दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका का हाथ अपने सिर से हटने के बाद पाकिस्तान ने अगर चीन के बल पर दक्षिण एशिया में अपनी हरकतें जारी रखने का मन बना रखा था तो उसकी यह योजना अजहर मसूद के साथ ही रसातल में जा चुकी है। आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर चीन है। ऐसे में भारतीय हितों की ज्यादा समय तक अनदेखी करने का जोखिम वह नहीं ले सकता।

रहा सवाल अजहर का नाम इस सूची में डाले जाने के फायदे का, तो आतंकवाद जैसी जटिल समस्या ऐसे एक–दो कदमों से हल होने वाली नहीं है। 11 वर्षों से ग्लोबल आतंकी घोषित हाफिज सईद आज भी पाकिस्तानी राजनीति का एक खास नाम है। लेकिन यह तो है कि ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी अब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की यात्रा नहीं कर सकते। उनके बैंक खातों से बेधड़क लेन–देन भी अब नहीं हो सकता। उनपर तेज नजर रखना सरकारी मशीनरी के लिए लाजमी है। कुल मिलाकर देखें तो भारत में लाखों रुपये का आरडीएक्स भेजना उनके लिए पहले जितना आसान नहीं होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में शांति की कामना करने वालों के लिए यह भी बड़ी बात है।

सूडोकु नवताल-5195

सरल

7	8	6		1		5		2
	9			8				3
1			6	9		7		
	3	8	2		1			
2	7	5				6	3	1
			5		7	2	8	
		9		7	4			6
8				2			5	
4		2		5		9	1	7

Jagrutidaur.com, Bangalore

सूडोकु नवताल -5194 का हल

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

2	9	5	3	1	4	6	8	7
3	6	1	2	8	7	4	9	5
8	4	7	5	9	6	3	2	1
5	7	4	1	6	2	8	3	9
1	3	6	9	4	8	5	7	2
9	8	2	7	3	5	1	4	6
6	2	8	4	7	1	9	5	3
4	5	3	6	2	9	7	1	8
7	1	9	8	5	3	2	6	4

अपना ब्लॉग

देश के कलाकारों पर पाबंदी का फैसला

उपमा सिंह। यह पहली बार नहीं है, मीटू जैसी जरूरी मुहिम हो या कठुआ में किसी मासूम पर ज्यादती या फिर पड़ोसी देश के कलाकारों पर पाबंदी का फैसला, चर्चित फिल्मी हीरोज हमेशा न्यूट्रल रहने की ही कोशिश करते हैं। कभी मामले की पूरी जानकारी नहीं होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेंगे, तो कभी ये सही मौका नहीं है कहकर बात टाल देंगे। हालांकि, इस बार उनकी खुद की इंडस्ट्री के लोग ही उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी याद करने की सलाह दे रहे हैं। नागरिक संशोधन कानून के विरोध में इंडस्ट्री का एक बुद्धजीवी तबका जोरशोर से आवाज उठा रहा है। अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, रिचा चड्ढा, स्वरा भास्कर, सुशांत सिंह, संध्या मृदुल, फरहान अख्तर, तिगमांशु धूलिया, अली फजल, महेश भट्ट, अश्विनी चौधरी जैसे फिल्ममेकर्स–ऐक्टर्स न केवल खुलकर इस भेदभावपूर्ण कानून का विरोध कर रहे हैं, बल्कि इंडस्ट्री के आइकन्स की चुप्पी पर सवाल भी उठा रहे हैं। शायद वे डरते हैं कि कहीं उन्हें सरकार के खिलाफ बोलने का खामियाजा न उठाना पड़ जाए। जैसे, ऐक्टर सुशांत सिंह को उठाना पड़ा।